



# संपादकीय

## मणिपुर में राहत में सुस्ती और सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल

मणिपुर में हिंसा की शुरूआत के करीब छह महीने बाद भी अगर राज्य सरकार वहाँ शांति कायम नहीं कर सकी है तो यह उसकी कार्यक्षमता पर ही सवाल है। मगर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हिंसा के शिकार लोगों को राहत मुहैया कराने के मामले में भी समय पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए और इसके लिए देश की दूसरी संस्थाओं को याद दिलाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर सरकार से राज्य में मई महीने में शुरू हुए जातीय संघर्षों में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को दस-दस लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है। आयोग ने यह आदेश भी दिया कि हिंसा में क्षतिग्रस्त घरों का मूल्यांकन किया जाए और छह सप्ताह के भीतर प्रत्येक पीड़ित को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। यानी जो काम सरकार को अपनी ओर से करना चाहिए था, उसे लेकर भी वह सजग नहीं है। क्या सरकार के इसी उदासीन रवैये की वजह से राज्य में आज भी बिगड़े हालात पर काबू पाना मुश्किल नहीं बना हुआ है? सरकार के काम करने की शैली का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वहाँ दो समुदायों के बीच शुरू हुए टकराव को एक लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद हालात पर काबू पाने के लिए कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। अब भी वहाँ हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। इस पहलू पर मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा जारी रखने पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार से हालात सामान्य करने के लिए रुपरेखा तैयार करने को कहा है। यह सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए कि वह राज्य में हिंसा की वजहें पहचान कर उसका हल निकालने के लिए जरूरी कदम उठाने में नाकाम रही, फिर बाद में जब कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा ने व्यापक शक्ति ले ली, तब भी उसे रोकने का लेकर कोई ऐसी पहल नहीं दिखी, जिसे दूरदर्शी कहा जा सके। नतीजा यह हुआ कि राज्य में पुलिस से लेकर सेना तक की तैनाती के बावजूद वहाँ हिंसा और अराजकता बनी हुई है। हालांकि मैतेई समुदाय को जनजाति श्रेणी में शामिल करने के मसले पर वहाँ विरोध का जो ज्वार उठा, उसमें यह साफ दिख रहा था कि यह कैसा रूप ले सकता है। मगर इतने संवेदनशील मुद्दे को भी सरकार ने शायद तात्कालिक प्रतिक्रिया मान लिया था। इसी उदासीनता का नतीजा था कि समूचे राज्य में अराजकता का माहौल बन गया और उसके बाद स्थिति पर नियंत्रण करना सरकार के लिए मुश्किल हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी शांति और निगरानी समितियां बना कर हल निकालने की कोशिश की गई, मगर उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जबकि इस मसले का अकेला समाधान कुकी और मैतेई समुदायों के बीच संवाद और उभेरे सवालों पर सहमति कायम करना है। मगर हिंसा से प्रभावित इलाकों में न केवल कार्रवाई को लेकर शिथिलता बरती गई, बल्कि सरकार और पुलिस पर पक्षपात करने के भी आरोप लगे। मानवाधिकार आयोग को एक निश्चित तारीख तक एक सौ अस्सी लोगों के मारे जाने की सूचना दी गई थी, लेकिन ऐसे सिर्फ तिरानबे लोगों के परिजनों को ही दस लाख रुपए मुआवजा दिया गया। इससे सरकार की कार्यशैली और उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि क्या वह राज्य में हिंसा को पूरी तरह रोकने और पीड़ितों को राहत मुहैया कराने को लेकर गंभीर है?

# रोजगार की सरहद और आरक्षण पर सरकार की सियासी सोच

अपने सियासी स्वार्थ साधने की कोशिश में अक्सर पार्टीयां और सरकारें संवैधानिक मर्यादाओं के परे जाकर भी बढ़े और फैसले कर जाती हैं। यही किया हरियाणा सरकार ने। तीन साल पहले उसने कानून बना कर तय कर दिया कि उन सभी निजी कंपनियों, संस्थानों और संस्थाओं को अपने यहां नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को पचहतर फीसद आरक्षण देना होगा, जिनमें दस से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनका वेतन तीस हजार रुपए से कम है। जिस तरह राजनीतिक दल पूरे देश में जातीय और क्षेत्रीय अस्पता के मुद्दे पर अपना जनाधार बनाने की कोशिश करते देखे जाते हैं, उसमें हरियाणा सरकार का यह कदम नया नहीं कहा जा सकता। अच्छी बात है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया। दरअसल, इस आरक्षण का बादा विधानसभा चुनाव के वर्क जननायक जनता पार्टी ने किया था। फिर जब सत्ता गठबंधन में शामिल हुई तो उसने यह कानून भी बना दिया। हर कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को रोजी-रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए। मगर इसके लिए संविधान में दिए गए समानता और जीवन जीने के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई सरहद नहीं बनाई जा सकती, जिसमें दूसरे इलाकों के लोगों का प्रवेश वर्जित हो। भारत में संघीय व्यवस्था है और इसमें हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस और रोजी-रोजगार के अवसर तलाश सकता है। कोई भी राज्य सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। मगर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए क्षेत्रीय अस्पता का हवाला देते हुए कई बार बाहरी लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों को भड़काने का प्रयास करते देखे जा चुके हैं। असम और महाराष्ट्र इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। असम में बिहारी मजदूरों पर यह कह कर हमला किया गया और उन्हें वहां से भगाने का प्रयास हुआ था कि उनकी वजह से असम के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। इसी तर्क पर महाराष्ट्र में भी दूसरे प्रदेशों से जाकर बसे या किसी रोजी-रोजगार में लगे लोगों पर हमले किए गए थे। इस संकीर्ण सोच को रोपने का अवसर उन सभी इलाकों में उपलब्ध होता है, जहां उद्योग-धंधे और रोजी-रोजगार के अवसर अधिक हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ऐसी विभेदकारी कोशिशें सफल नहीं हो पातीं। हरियाणा में भी उद्योग-धंधे बहुत हैं, जहां दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आकर लोग काम करते हैं। इस तरह जजपा के लिए हरियाणा के लोगों में यह भाव भरना आसान हो गया कि स्थानीय लोगों का हक बाहरी लोग छीन रहे हैं। निजी कंपनियां और संस्था-संस्थान अपनी जरूरत के हिसाब से कौशल आदि का आकलन करते हुए कर्मचारी नियुक्त करते हैं। उसमें पचहतर फीसद स्थानीय लोगों को भरने की अनिवार्यता लागू करने से उन्हें कुशल कर्मचारियों के चुनाव में अड़चन आना स्वाभाविक है। इसलिए कंपनियों ने इस कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया था कि इससे उनकी उत्पादकता और कार्य-कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे संविधान के मूल उद्देश्य का हनन तो हो ही रहा था। अगर सभी राज्य सरकारें इसी संकुचित सोच के साथ काम करने लगें, तो देश का संघीय ढांचा ही टूट जाएगा। हमारी मिश्र और समावेशी संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। रोजगार के लिए योग्यता और कुशलता के बजाय क्षेत्रीयता कोई पैमाना नहीं होना चाहिए।

# स्वदेशी के मंत्र ने भारत के आर्थिक विकास को नये पंख लगा दिये हैं



# आओ हल्दी की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें

वैशिक स्तर पर पूरी दुनियां को विश्वास हो चुका है कि भारत के हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। 40-50 सालों से लटके कामों को सफलतापूर्वक नए जोश के साथ आगे बढ़कर मंजिल तक पहुंचा जा रहा है। वहीं आज भारत ने हर क्षेत्र को विकसित करने के लिए उनकी जड़ों तक पहुंचकर समस्याओं का हल ढूँढ़ने में भिड़ गया है जिसके लिए उस उत्पाद या क्षेत्रों का राष्ट्रीय बोर्ड गठन कर उसका विकास किया गया है, जिसका उदाहरण चाय बोर्ड सहित आने अनेक बोर्डों का गठन किया गया है और अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी प्रदान कर अधिसूचित हुआ है। बता दें इसके लिए अनेक वर्षों से किसानों की मांग जारी थी और 15-20 सालों से आंदोलन कर रहे थे, जिसमें इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को लेकर प्रण लिया था कि जब तक बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे, अब इस बोर्ड के गठन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित कर अधिसूचित किया गया है। बोर्ड के गठन से अब अनेक स्थानों, हल्दी उत्पादन के दूरदराज दुर्लभ स्थान या अनजान स्थान का संज्ञान लेकर वहीं हल्दी उत्पादन में तकनीक की सहायता कर उत्पादन बढ़ाया जाएगा। असमय आ गया है कि जिस क्षेत्र हल्दी उगने का एटमॉस्फेर है और हल्दी की फसल अच्छी निकाल की आमना है, वहां किसानों व हल्दी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सभी खाद्य औषधि सहित अन्य सभी प्रयोग में आने वाली एवं वस्तु है जिसमें किसानों को अच्छी कमाई करने की उम्मीद है, साथ ही बोर्ड की पूरी मदद मिलने व रणनीति तैयार की गई है। बोर्ड इसका संज्ञान लेकर इसका विकास करेगा तो नए ऊंचे आयामों व प्राप्ति किसानों को होगी। चूंकि हल्दी किसानों के लिए एक कमाई वाला फसल है और अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को भी अधिसूचित किया गया है, इसलिए आज ही मीडिया में और पीआईबी : उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, आओ हल्दी की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें अंतरराष्ट्रीय स्तरपर हल्दी के न बाजार विकसित करने में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना समय की मांग है।

कर्का कर्का कर्का कर्का हो हो हो हो इस प्रो हो खेसि है, ला अदेह इस खेकर हेह कर हर शुशु हम हो उठ हेद 20 याकिर्का

माई वाली फसल होने को, जाने के करें तो, बताते चलें कि हल्दी खेती को कमाई वाली फसल हा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत से कार्यों में इस्तेमाल ने वाली फसल है। जिसकी मांग बेशा बनी रहती है। हल्दी का उत्पादन अधिक मात्रा में इस्तेमाल मसाले, औषधि, ब्यटी डक्टस व अन्य कई उत्पादों में होता है। इसके साथ ही हल्दी की खेती की दौरान अधिक पानी या फिर चार्चाई की आवश्यकता नहीं होती ये एक ऐसी फसल है जो कम जागत में उग सकती है और इससे अच्छी आमदनी की जा सकती है। इस के लाभगम हर घर में हल्दी का उत्पादन किया जाता है। इसकी खेती कर किसान भाई अच्छा पैसा मांग सकते हैं। यदि हम एक बेटेयर जगह में हल्दी की खेती रखें की सोच रहे हैं तो करीब-रीब दस हजार रुपये के बीज, दस जार रुपये की खाद व मजदूरी लक्क जो उस समय लागू हो वह नको देना होगा। हल्दी की खेती से ने वाली आय मुख्य रूप से खादन पर निर्भर होती है। एक बेटेयर में हल्दी का औसत उत्पादन 20-25 किंवंटल तक का होता है। देह हल्दी का भाव दो सव रुपये लगते हैं, तो एक हेक्टेयर में हल्दी खेती से करीब 5 लाख तक की

मार्ह की जा सकती है। बाजार में हल्दी की काफी डिमांड है। भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी हल्दी की पी मांग है। हम हल्दी को निलाइन प्लेटफार्म के जरिए भी छोटे दामों में बेच सकते हैं। हल्दी खेती करने के लिए अच्छी जल कासी वाली मिट्टी को चुनें। इसके तीव्री करने के लिए जैविक खाद का उत्पाल करें। हल्दी की खेती के दौरान कीटों और बीमारियों से बाव के लिए उचित उपाय करें। सप्ल को सही समय पर खेत से काल लें।

साथियों वाल अगर हम राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित करने की करें तो, भारत सरकार ने ट्रीट्य हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी पादों के विकास और वृद्धि पर कास करेगा। बोर्ड हल्दी से उचित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा। हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसला बोर्ड और अन्य कारी एजेंसियों के साथ अधिक अन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जनल टर्मिक बोर्ड (राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड) के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बारे में जनकारी देते हए

योगी मंत्री का कहना है कि इसका लक्ष्य है कि भारत 2030 प्रतिवर्ष एक बिलियन डॉलर हल्दी का निर्यात विशेषा में किया गया। नेशनल टर्मिक बोर्ड नामकाज के बारे में जानकारी देते केंद्रीयमंत्री ने बताया कि कोरोना पामारी के बाद दुनियां ने हल्दी के खेत को समझ लिया है। भारत कार भी इसके उत्पादन उपभोग और निर्यात को बढ़ावा देना चाहती यह बोर्ड इसमें मदद करेगा। के साथ ही बोर्ड देश में हल्दी के हल्दी उत्पादों के विकास और लाभों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बोर्ड की गोश्ठी और अन्य सरकारी सियों के साथ अधिक समन्वय सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ दुनिया भर में हल्दी की खपत ने की बहुत संभावनाएं हैं और इसकी मदद से हल्दी की प्रतिरूपकाता और खपत बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, उत्पादों में रिसर्च करने और विकास को बढ़ावा देने का काम किया गया। बोर्ड विशेष रूप से मूल्य धर्नां से अधिक लाभ प्राप्त करने लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। बोर्ड गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को भी बढ़ावा देगा। इन्हीं नहीं बोर्ड हल्दी को सुरक्षा प्रदान करेगा और उपयोगी दोहन के लिए भी कदमउठाएगा। बोर्ड के गठन को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री ने पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे हमेशा किसानों के हित में काम करते हैं। हल्दी बोर्ड का गठन भी इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। उनका कहना है कि इससे कई किसानों की लंबी मांग पूरी हो गई जो लगभग 15 से 20 साल से इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे और अपने मांग के समर्थन में उन किसानों ने चप्पल न पहनने का फैसला लिया था।

साथियों बात अगर हम हल्दी के प्रति जागरूकता बढ़ाने बोर्ड के कार्यों की करें तो, हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याण लाभों पर विश्व भर में महत्वपूर्ण संभावनाएं और रुचि है, जिसका लाभ बोर्ड जागरूकता और खपत बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, उत्पादों में रिसर्च करने और विकास को बढ़ावा देने का काम किया गया। बोर्ड विशेष रूप से मूल्य धर्नां से अधिक लाभ प्राप्त करने लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता

एप्रील्सो शिरकर सम्मेलन में अमेरिका-चीन की वैश्विक मुद्दों पर हिपक्षीय वार्ता से ढुनियां हैरान

वैश्विक स्तर पर आज दुनियां में ताकतवर देश के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है जो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता तैयार कर रहा है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों में स्थिति ऐसी बन रही है कि गुटबाजियों को बल मिल रहा है और विकसित ताकतवर देश अपना वर्चस्व स्थापित करने सामने या फिर पर्दे के पांछे अपना डंका का जरूर बजाने की कोशिश करते हैं, जो उकसाने की कार्यावाही के रूप में परिभाषित हो जाती है, यही से लड़ाई का परिया पड़ जाता है जो विश्वयुद्ध की लड़ाई में तब्दील हो जाता है। पृथ्वी पर दो महा विश्वयुद्ध हो चुके हैं और अब रूस यूक्रेन इसराइल हमास युद्ध अमेरिका - रूस - चीन की लुका छिपी, भारत पाकिस्तान चीन की जहोजहद अनेक देशों की सेना द्वारा सत्ता पलट कर काबिज सहित अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं जिससे विश्व शांति कोठेरे पहुंचती है, इसे समाज करने के लिए ताकतवर देश पड़ोसी देशों सहित आपसी मतभेदों वाले देशों को आपस में मिल बैठ मतभेदों के मुद्दों पर चर्चा करके वैश्विकस्तर पर शांति स्थापित करना वर्तमान समय की मांग है जिसकी शरूआत हो गई है क्योंकि दिनांक 11 - 1 नवंबर 2023 को अमेरिका के सेंगे फ्रांसिस्को में हुए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन धुर विरोधी अमेरिका चीन वैश्विक मुद्दों पर विपक्षीय वार्ता का दुनियां का चौंका दिया है और संदेश भी दिया है कि आपसी वार्ता कितनी महत्वपूर्ण है, चूंकि एप्रिल में यह शुरूआत हो चुकी है जिसमें मौजूदा तनावपूर्ण माहौल पर पान के छीटें मारने का काम किया गया इसलिए आज हम मीडिया उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, वैश्विक तनाव कम कर शांति स्थापित करने बड़े देशों व द्विपक्षीय सकारात्मक वार्ता होने वर्तमान समय की मांग है।

साथियों बात अगर हम 1 नवंबर 2023 को एप्रिलीसी के 3 वें शिखर सम्मेलन में अमेरिका और चीन के समकक्ष राष्ट्रपतियां द्वारा द्विपक्षीय वार्ता की करते तो अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति की बुधवार को हुए मुलाकात कई वजहों से अहम रही अबल तो इसने दुनिया के मौजूदा तनावपूर्ण माहौल पर पानी के छीटें मारने का काम किया है। दूसरी बायह कि दिनिया के दो सब-

ताकतवर देशों के प्रमुखों की इस मुलाकात के दौरान कूटनीतिक संतुलन साधने की कुशलता अपने बेहतरीन रूप में नजर आई। दोनों नेता ऐसे समय में मिल रहे थे, जब दुनिया रूस-यूक्रेन और इस्टाइल-हमास युद्ध की दोहरी चुनौतियों से जूझ रही है और दोनों ही मामलों में चीन और अमेरिका की सहानुभूति परस्पर विरोधी खेमों के साथ जुड़ी है। जहां अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है, वहीं चीन रूस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर, अमेरिका इस्टाइल के आत्मरक्षा के अधिकार का मुखर प्रवक्ता बना हुआ है तो चीन गाजा में नागरिक आबादी पर हमले की निंदा करने में आगे है। इन तात्कालिक मुद्दों के अलावा भी पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर दूरी इतनी बढ़ गई कि उस दुनिया की दो सबसे बड़ी इकानमी के बीच ट्रेड वॉर कहा गया। साउथ चाइन सी और ताइवान जैसे मसलों पर चीनी आक्रामकता और उस पर रोक लगाने की कोशिशें तो अपनी जगह थीं ही। इन सबके कारण दोनों पक्ष आपसी दूरी को कम करना जरूरी समझ रहे थे। जैसा कि मुलाकात के बाद जारी बयान में संकेत दिया गया

कि ताइवान, टेक्नॉलॉजी, साउथ चाइना सी या रूस को चीनी सहायता जैसे मसलों पर तनाव को बढ़ाने देने से उसके संघर्ष का रूप लेने का खतरा है। इसी खतरे को टालने की दिशा में एक ठोस प्रगति यह हुई कि बैठक में सर्वोच्च स्तर पर बातचीत का चैनल हमेशा खुला रखने का फैसला किया गया। तय हुआ कि जब भी जरूरत होगी दोनों राष्ट्रपति फोन पर एक-दूसरे से बात कर लिया करेंगे। ऐसे संकेत मिले कि खास तौर पर आर्थिक मसलों पर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में उभरे मतभेद आने वाले समय में कुछ कम होते दिखेंगे। मगर इस बीच अंतरराष्ट्रीय सामरिक समीकरण जो रूप ले चुके हैं उसे देखते हुए न तो ये दोनों देश एक-दूसरे के ज्यादा करीब आ सकते हैं और न ही ऐसा परस्परण बनने दे सकते हैं। इस बात को लेकर सरकार भी चार घंटे चली इस मुलाकात के दौरान साफ नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन अच्छे मेजबान की भूमिका में रहे और यह बताया कि कैसे शी चिनफिंग के साथ उनके बरसों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन उन्हें पुराना दोस्त बताने की रवायत से सचेत रूप में बचे रहे। यही नहीं इस मुलाकात के कुछ घंटे के अंदर ही शी चिनफिंग को तानशाह बताने वाला अपना पुराना बयान भी देहरा दिया। साफ है कि दोनों महाशक्तियों के रिश्तों के समीकरणों में तत्काल कोई नाटकीय बदलाव नहीं आने वाला।

साथियों बात अगर हम दोनों ताकतवर देशों की वार्ता से संबंधों में खटास कम होने की करें तो, अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से संबंधों में खटास बनी हुई है। दोनों देशों के बीच कुछ तनाव और दूरियों को कम करने के मकसद से इस साल पहली बार चीनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की सेन फ्रासिस्को में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों राष्ट्रध्यक्षों ने जहां आपसी सौहार्द को बढ़ाने से लेकर इजरायल हमास युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध और ताइवान के तनाव आदि जैसे खास मुद्दों पर बातचीत की लेकिन इस मुलाकात को ताइवान के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान यूएस प्रेजिडेंट ने अपने चीनी समकक्ष के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की, इन नेताओं की द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ता पर भारत समेत परी दलिया की निगाहें विकल्प नहीं हैं।









**मिर्गी** संबंधी, करियर, सामाजिक स्थिति पर डालती है असर

कोचिंग, (वार्ता)। केंद्र में विशेषज्ञों ने बताया कि मिर्गी संबंधी, करियर, वित्त और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। कोचिंग के अमरा अस्पताल के प्रभुव्य न्यूरोलॉजिस्टों में से एक ने मिर्गी के बढ़ते रोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मिर्गी के समान भारी कोरोना की आशंका जलते हुए बढ़ती उम्र की आवादी की वर्तमान प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। मिर्गी के लगभग 80 प्रतिशत मरीज निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, खासकर गरीब सामाजिक-आर्थिक तबके में। कई नव निदान मिर्गी रोगी बढ़ रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों में 22 प्रतिशत का इलाज नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'मिर्गी में से एक है, और भारत में ही, हारे पास एक करोड़ से अधिक मरीज मिर्गी से प्रभावित है।' उन्होंने कहा, 'मिर्गी भारी कोरोना की समाना करना पड़ रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों में 22 प्रतिशत का इलाज नहीं किया जा रहा है।'

उन्होंने कहा कि मिर्गी में हाथ और पैर का मरोड़ना, गिरना, और मूँह से झांग निकलना सहित कई लक्षण पाए जाते हैं। विशेष रूप से, दौरे अलग-अलग हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बोलेरो में अचानक रुकावा और खाली घूमना, आंखों का तेजी से झपकना और भ्रम, अस्पष्ट भ्रम, दृश्य विविधता के रूप में प्रकट होते हैं। डा. गोपीनाथ भाटियों को दृढ़ करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि कारों के आधार पर दवाओं को अनुकूलित किया जाता है।' उन्होंने कहा कि शेष 30 प्रतिशत के लिए, सर्विकल विकल्प संभव है। अफसोस की बात है, देखाल करने वालों को अस्त्र मिर्गी से पीड़ित परवार के सदस्य की देखभाल में मदद करने के लिए ज्ञान की कमी होती है। आम जनता ने शिक्षा और जागरूकता की उल्लेखनीय कमी है कि मिर्गी से पीड़ित लोगों का समर्थन कैसे किया जाए।'



मिर्गी एक तीव्रका संबंधी विकार है, मानसिक विकार नहीं। मिर्गी किसी भी उम्र में विकसित हो सकती है और दौरे विभिन्न रूपों में प्रवर्त हो सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'मिर्गी का प्रबंधन मुख्य रूप से दौरे-रोधी दवाओं पर निर्भर करता है, जिसमें 70-75 प्रतिशत रोगियों में सक्रात्मक प्रतिक्रिया देखी गई है। मिर्गी के प्रकार, उम्र और लिंग, रोगी के व्यवसाय जैसे

कारों के आधार पर दवाओं की उपलब्धता और खाली घूमना, आंखों का तेजी से झपकना और भ्रम, अस्पष्ट भ्रम, दृश्य विविधता के रूप में प्रकट होते हैं। डा. गोपीनाथ भाटियों को दृढ़ करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि

हारे पास एक करोड़ से अधिक मरीज मिर्गी से प्रभावित हैं। भारत को इलाज में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों में 22 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत का इलाज नहीं किया जा रहा है।'

## 72 वर्ष की हुई जीनत अमान

**मुंबई** (वार्ता) बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री जीनत अमान आज 72 वर्ष की हो गई। जीनत अमान का जन्म 19 नवम्बर 1951 को जर्मनी में हुआ। उनके पिता अमानउल्लह ने पुरालोआजम और पाकिस्तानी सुरहद फिल्मों में बौरै लेखक काम किया था। महज 13 वर्ष की उम्र में जीनत के पिता से पिता का साथा उठ गया। तब उनकी मां उन्हें जर्मनी लेकर चली गई। लगभग पंच वर्ष तक जर्मनी में रहने के बाद महज 18 साल की जीनत मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद जीनत ने सेंट जेवियर कालेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की



जीनत अमान को प्रारंभिक सफलता वर्ष 1971 में प्रदर्शित फिल्म 'हरे रामा हरे कृष्णा' से मिली। इस फिल्म में जीनत अमान ने देवानंद की बहन की भूमिका निभाई थी।

और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के मशहूर कालेज कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। जीनत अमान ने अपने करियर की शुरुआत मशहूर परिवार 'फेमिना' से बौरै पकार के रूप में उनका नाम इससे उच्चत गया और वह मार्डिना के क्षेत्र में उत्तर गई। इसके बाद जीनत अमान ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें वह दूसरी उप विजेता रहीं और बाद में उन्हें बौरै एप्पीलिंग फिल्म 'हलचल' से किया गया।

वर्ष 1971 में ही जीनत को एक बार पिर से ओ-पी-रलॉन के साथ फिल्म 'हीमांग में काम करने का पौका मिला। दुर्भाग्य से उनकी दोनों पिल्लै टिक खिड़की पर विफल रहीं। जीनत अमान को प्रारंभिक सफलता वर्ष 1971 में प्रदर्शित फिल्म 'हरे रामा हरे कृष्णा' से मिली। इस फिल्म में जीनत अमान ने देवानंद की बहन की भूमिका निभाई थी। फिल्म में दमदार अभिनय के लिए जीनत अमान को प्रशंसित फिल्म 'यादी' को बात से बाकी। बैहरीन सौत-संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की कामयादी ने जीनत अमान को स्टार के रूप में ख्यालित किया गया। वर्ष 1973 में प्रदर्शित फिल्म 'यादी' को बात से बाकी। बैहरीन सौत-संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की कामयादी ने जीनत अमान को स्टार के रूप में ख्यालित किया गया। वर्ष 1978 में जीनत अमान को महान शा मैन राजकूपर की फिल्म 'सल्यम शिवम सुंदरम' में काम करने का पौका मिला।

### 'धूम' के निर्देशक संजय गढ़वी का

#### 56 साल की उम्र में निधन

**मुंबई** (भाषा)। फिल्म 'धूम' के निर्देशक संजय गढ़वी का रोगिवार सुबह वहां उनके आवास पर निधन हो गया। उनकी बड़ी बेटी संजीना ने यह जानकारी दी। वह 56 वर्ष के थे। जीनत अमान ने बात बाद अपना 57वां जन्मदिन मनाया। उन्हें यशराज फिल्म की 'धूम' सीरीज की फिल्मों 'धूम' (2004) और 'धूम 2' (2006) के निर्देशक के लिए जाना जाता है। गढ़वी की बेटी के अनुसार निर्देशक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। जीनत अमान के अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। जीनत अमान के अभिनेत्री का बैहरीन नायर सुहैल द्वारा दिनें बाल नायर से जीवित रही थी। इसके बाद वर्ष 1999 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें वह प्रथम चुनी गई। इसके बाद वर्ष 1999 में मिस इंडिया सेन के प्रधारित फिल्म 'दरतक से की', लेकिन वह फिल्म कोई खास कामल नहीं दिया। इसके बाद सुष्मिता सेन को वर्ष 1997 में सन्नी टेपोल के अपेजिट जोर से काम करने का अवकर मिला, लेकिन वह फिल्म भी टिक खिड़की पर असफल रही।

वर्ष 1999 सुष्मिता सेन के करियर के लिये अहम साल साबित हुआ। इस वर्ष उनकी बीबी नंबर वन और सिर्फ तुम जैसी सुपरहिट फिल्म प्रदर्शित हुई।

बीबी नंबर वन के लिए सुष्मिता सेन को माली शूटिंग के दौरान लाली थीं। एक फैन

ने टिप्पणी की, वित्तना सुरु तो एक अच दर्शक

ने लिखा, खबरसूत डास और मूस... ऐसा

लग रहा है जैसे श्रेदोवी मैम डास कर रही है।

माली की शूटिंग के दौरान लाली थीं। एक फैन

ने टिप्पणी की, वित्तना सुरु तो एक अच दर्शक

ने लिखा, खबरसूत डास और मूस... ऐसा

लग रहा है जैसे श्रेदोवी मैम डास कर रही है।

सुष्मिता सेन ने अपने सिनेकरियर की शुरुआत वर्ष 1996 में प्रदर्शित फिल्म 'सल्यम' से की, लेकिन वह फिल्म कोई खास कामल नहीं दिया। सुष्मिता सेन को वर्ष 1997 में सन्नी टेपोल के अपेजिट जोर से काम करने का अवकर मिला, लेकिन वह फिल्म भी टिक खिड़की पर असफल रही।

वर्ष 1999 सुष्मिता सेन के करियर के लिये अहम साल साबित हुआ। इस वर्ष उनकी बीबी नंबर वन और साथी नंबर वन रही। एक फैन

ने टिप्पणी की, वित्तना सुरु तो एक अच दर्शक

ने लिखा, खबरसूत डास और मूस... ऐसा

लग रहा है जैसे श्रेदोवी मैम डास कर रही है।

माली की शूटिंग के दौरान लाली थीं। एक फैन

ने टिप्पणी की, वित्तना सुरु तो एक अच दर्शक

ने लिखा, खबरसूत डास और मूस... ऐसा

लग रहा है जैसे श्रेदोवी मैम डास कर रही है।

माली की शूटिंग के दौरान लाली थीं। एक फैन

ने टिप्पणी की, वित्तना सुरु तो एक अच दर्शक

ने लिखा, खबरसूत डास और मूस... ऐसा

लग रहा है जैसे श्रेदोवी मैम डास कर रही है।

माली की शूटिंग के दौरान लाली थीं। एक फैन

ने टिप्पणी की, वित्तना सुरु तो एक अच दर्शक

ने लिखा, खबरसूत डास और मूस... ऐसा

लग रहा है जैसे श्रेदोवी मैम डास कर रही है।

माली की शूटिंग के दौरान लाली थीं। एक फैन

ने टिप्पणी की, व



